>

Title: Need to formulate an effective policy to address the issue of malnutrition in the country.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सभी माननीय सदस्यों ने जैसी चिंता व्यक्त की, उसी पर मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। यह सचमुच राष्ट्रीय शर्म का विषय है कि दुनिया की दूसरी सबसे तेज बढ़ती अर्थ व्यवस्था वाले देश में 42 प्रतिशत बच्चों का वजन सामान्य से कम है। कई मायनों में महिलाएं भी कुपोषित हैं। अब जब खुद प्रधान मंत्री जी ने भूख और कुपोषण पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए यह कहा है कि तेजी से प्रगति कर रहे देश के लिए पोषण का स्तर सामान्य से कहीं अधिक कम होना अस्वीकार्य है। कुपोषण की समस्या के समाधान में आई.सी.डी.एस. जैसी योजनाओं पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। आई.सी.डी.एस. में कुपोषण में सिर्फ 2.7 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से गिरावट ला पा रही है। पिछले 7 वर्षों में कुपोषित बच्चों के प्रतिशत में केवल 11 प्रतिशत की कमी आई है। इस समस्या से निपटने के जैसे उपाय किए जाने चाहिए, वे अपर्याप्त हैं। बेहतर होगा कि भारत सरकार इस समस्या को लेकर चेत जाती क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास सूचकांक रपट लगातार यह कह रही है कि भारत में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की स्थिति अनेक निर्धन अफ्रीकी देशों से भी गई गुजरी है।

मैं कहना चाहती हूं कि राज्य सरकारों को कहीं अधिक सतर्कता और सजगता का परिचय देना होगा, जैसे गुजरात पैटर्न की तरह कुपोषण के लिए जंग छेड़ी गई है। निश्चित रूप से कुपोषण का मूल कारण सेहत के प्रति अज्ञानता भी है एवं निर्धन तथा वंचित तबकों के पास पोषण योग्य आहार की कमी भी एक विडम्बना है। विभिन्न स्रोतों से यह सामने आ रहा है कि देश में कुपोषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर भंडारण का अभाव स्पष्ट है। भीख और कुपोषण का सामना तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक सभी कमजोर कड़ियों को मजबूत नहीं किया जाता।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि मिड डे मील, पीडीएस का फायदा भी इन्हें चलाने वाले ही उठा रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि कुपोषण को खत्म करने हेतु सक्षम नीति एवं कठोर कदम उठाए जाएं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती जयश्रीबेन द्वारा उठाए गए विषय से अपने को सम्बद्ध करता हूं।